ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

वैज्ञानिकों ने पाम ऑयल के कचरे से बनाई इको-फ्रेंडली पैकेजिंग सामग्री

रविवारीय, 22 - 28 नवंबर 2020 वर्ष- दो, अंक-16, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

नेतरहाट विद्यालय को समृद्ध बनाए रखने में सरकार पूरा सहयोग करेगी:मुख्यमंत्री

नेतरहाट आवासीय विद्यालय ना सिर्फ झारखंड बल्कि देश के गौ-रवशाली और प्रख्यात विद्यालय के रूप में जाना जाता है । इस विद्यालय के गौरव को बनाने और बताने की जरूरत नहीं है । सिर्फ थोड़ा आकार देने की जरूरत है, ताकि विश्व के पटल पर इस विद्यालय को पहचान दिलाई जा सके । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय परिसर का अवलोकन किया । विद्यालय परिवार की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थापना काल से ही यह विद्यालय नई ऊंचाइयों को छू रही है । इस विद्यालय की अपनी एक अलग ही पहचान है । बस इस पहचान को आगे भी कायम और संरक्षित रखना है । इस विद्यालय की समृद्ध व्यवस्था को बनाए रखने में सरकार पूरा सहयोग करेगी ।

अभिनंदन समारोह में प्राचार्य संतोष कुमार सिंह ने विद्यालय परिवार की ओर से मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया

झारखंड सरकार ने जलाशयों पर छठ के आयोजन पर लगाये रोक को जनविरोध में हटाया था, अंततः लोगों के सूझ - बूझ

सावधानी से संपन्न हुआ छठ महापर्व

संवाददाता

रांची : कोविड-19 का संकट सिर्फ महामारी के रूप में ही नहीं है बल्कि इसका असर देश के सामाजिक ताने बाने के अलावा पर्व त्यौहारों पर भी पड़ रहा है। भारत जैसे देश में जहां प्रत्येक महिने और ऋतुओं के अनुसार पर्व त्यौहार, उत्सव मनाये जाते हैं उस पर भी कोविड -19 का दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके कारण सरकार, प्रसाशन भी किंकर्त्व्यविमूढ़ हो जा रहा है। इन सबके बावजूद लोगों ने सकारात्मक पहल की और छठ महापर्व को कम भीड़ भाड़ के साथ सुरक्षात्मक तरीके से मनाया। आम वर्षों की अपेक्षा इस साल छठ घाटों पर बहुत कम भीड़ रही और ज्यादतर लोगों ने इस महापर्व को अपने घरों एवं छतों पर ही मनाया।

झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण के भय से छठ पर्व को नदियो, झीलों, तालाबों में मनाने पर रोक लगा दी थी। जिसका सरकार के अपने ही लोगों तक ने विरोध किया और जनविरोध भी सामने आने लगा। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर आक्रोशित था वहीं सोशल मीडिया में भी सरकार के इस निर्णय की खिंचाई होने लगी थी। अंततः सरकार ने दबाव में जलाशयों पर सार्वजनिक छठ आयोजन पर रोक के अपने निर्णय को वापस ले लिया था। साथ ही एहतियात बरतने की बातें भी कहीं थी। सरकार के इस आग्रह का और लोगों के अपने विवेक का ही असर रहा कि लोगों ने ज्यादा भीड़ से परहेज किया और

सरकार की मंशा गलत नहीं थी

झारखंड सरकार के जलाशयों पर छठ महापर्व के आयोजन पर रोक को लेकर विरोध में कई तरह की बातें की गयीं, पर यह समझने की चीज है कि कोरोना के खतरे को देखते हुये सरकार ने यह कदम उठाये थे न कि किसी आयोजन पर रोक लगाने के लिये। लेकिन लोगों, सहयोगियों के विरोध में सरकार ने इस रोक को वापस ले लिया

लापरवाही से बचे रहे। जिन घाटों डैमों पर हजारो की संख्या में लोग एकत्र होते थे वहां बहुत ही कम संख्या में लोग पहुंचे और सुरक्षित दूरी बना कर इस महापर्व का आयोजन किया।

भयंकर प्रदूषित हैं ज्यादतर नदियां, तालाब व झीलें

प्रदूषण और खतरे पर अक्सर ही आस्था भारी पड़ती है। छठ महापर्व में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। यह हमारे लिये गर्व का विषय है कि छठ महापर्व स्वयं प्रकृति की पूजा है। सूर्योपासना के माध्यम से ही नदियों, तालाबों की सफाई भी हो जाती है, पर यह दुखद बात है कि हमारे ज्यादतर तालाब, झीलें, नदियां प्रदूषित हैं। हम सालों भर इन्हें प्रदूषित करते हैं और छठ महापर्व के समय सिर्फ इसके किनारों को साफ कर घाट बनाते हैं, लेकिन जल तो प्रदूषित ही रहता है।

बेहतर हो कि लोग इस चीज को समझें और छठ महापर्व के बाद भी इन जलाशयों की साफ सफाई का सालों भर ध्यान रखें तभी तो पर्व त्यौहारों की भी रौनक बरकरार रहेगी।

ज्यादतर छतों पर ईंटों और प्लास्टिक के उपयोग से बना अस्थायी हौदा

भले सरकार ने जलाशयों पर महापर्व के आयोजन पर लगी रोक हटा ली थी लेकिन अधिकतर लोगों ने इस रोक के हटने बावजूद इस वर्ष तालाबों, नदियों का रूख नहीं किया और अपने छतों पर ही ईंट को सजा कर प्लास्टिक से ढ़क कर उसमें पानी भर दिया और छठ व्रत मनाया। ऐसा कोरोना के संकट से बचने के साथ ही प्रदूषित हो चुके नदियों तालाबों मेंभीड़ और घाटों की मारामारी से बचाव के लिये भी किया गया।

हाल के कुछ सालों में रांची में बढती आबादी के कारण उपलब्ध जलाशयों , नदियों तालाबों के किनारे छठ घाटों की भी कमी हो गयी है। इस कारण से घाटों पर जगह के लिये टकराव और बहुत ज्यादा भीड़ का होना आम बात है, लेकिन इस वर्ष कोरोना के भय से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई।

अमेरिका समुद्र प्रदूषण फैलाने में नंबर तीन

अमेरिका ने पर्यावरण में 22 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक फैलाया, इसमें से 15 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक समुद्र के तटों में फेंक दिया। एक नए अध्ययन से पता चला है कि अमेरिका तटीय प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाले देशों में तीसरे स्थान पर है। इसके प्लास्टिक कचरे के निर्यात के साथ-साथ देश में कूड़े की अवैध डंपिंग बढ़ रही है।

नए शोध ने इस धारणा को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका अधिकतर कूड़े का सही तरीके से प्रबंध कर रहा है। जिसमें कूड़े, प्लास्टिक कचरे को एकत्र करना और ठीक से लैंडफिल में डालना तथा रीसाइक्लिंग करना शामिल है। एक पुराने अध्ययन ने 2010 के आंकड़ों का उपयोग करके अमेरिका को प्लास्टिक कूड़े के निर्यात में 20वें स्थान पर रखा था। जबकि यह कचरे का सहीं से प्रबंधन न करने के कारण समुद्र के प्लास्टिक प्रदूषण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। 2016 में अमेरिका के द्वारा प्लास्टिक कचरे का निर्यात चीन, हांगकांग एसएआर, फिलीपींस, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, आयरलैंड और फ्रांस में सबसे अधिक किया गया। यह अध्ययन साइंस एडवांस में प्रकाशित हुआ है।

चीन और इंडोनेशिया फैलाते हैं समुद्र में सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषण

सी एजुकेशन एसोसिएशन, डीएसएम पर्यावरण सेवा, जॉर्जिया विश्वविद्यालय और महासागर संरक्षण के वैज्ञानिकों ने अमेरिका में रीसाइक्लिंग के लिए एकत्र किए गए आधे से अधिक प्लास्टिक का हिसाब लगया। जिसमें कहा गया है कि 39.1 लाख (3.91 मिलियन) मीट्रिक टन में से 19.9 लाख (1.99 मिलियन) मीट्रिक टन प्लास्टिक को रीसाइक्लि कर विदेशों में भेज दिया गया। इस आंकड़े का अनुमान लगाने के लिए उन्होंने 2016 से प्लास्टिक कचरे के उत्पादन के आंकड़ों का उपयोग करते हुए, नवीनतम उपलब्ध वैश्विक संख्या का उपयोग किया। इसमें से 88 फीसदी निर्यात किया गया प्लास्टिक ऐसे देशों में भेजा गया जो इसे सहीं ढंग से प्रबंधित, रीसायकल या निपटान नहीं कर सकते है। और 15-25 फीसदी के बीच बहुत खराब या दूषित था, जिसका अर्थ है कि इसे अब रीसायकल नहीं किया जा सकता है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि लगभग 1 मिलियन मीट्रिक टन तक अमेरिका द्वारा उत्पादित प्लास्टिक कचरे ने पर्यावरण को सबसे अधिक प्रदूषित कर दिया है।

सी एजुकेशन एसोसिएशन में ओसेनोग्राफी (समुद्र विज्ञान) के प्रोफेसर डॉ. कारा लैवेंडर लॉ ने कहा कि सालों से, हमने जितने भी प्लास्टिक को वातावरण में फैका, इसके बाद रीसायकल कर ऐसे देशों को निर्यात कर दिया गया जो स्वयं अपने कचरे का प्रबंधन करने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। इस सब में अमेरिका की सबसे अधिक भूमिका है। हमारे पूरे प्लास्टिक कचरे में से अधिकतर को रीसायकल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह खराब, दूषित या रीसायकल करने लायक नहीं होता है, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इसका अधिकतम भाग पर्यावरण में प्रदूषण फैलाता है। अध्ययनकर्ताओं ने 2016 के आंकड़ों का उपयोग करते हुए, यह भी अनुमान लगाया कि पूरे प्लास्टिक कचरे का 2-3 फीसदी अमेरिका में उत्पन्न हुआ। जो कि 9.1 लाख (0.91) से 12.5 लाख (1.25 मिलियन) मीट्रिक टन के बीच है।

बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतलों में मिला उच्च स्तर का माइक्रोप्लास्टिक

एजेंसियां

पॉलीप्रोपाइलीन-बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतल में 1.6 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक के कण और प्रति लीटर छोटे नैनोप्लास्टिक के खरबों कण निकल सकते हैं।

पॉलीप्रोपाइलीन आधारित उत्पादों को आमतौर पर भोजन तैयार करने और भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इनसे माइक्रोप्लास्टिक निकलता है जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक माना जाता है।

नए शोध में पता चला है कि बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतलों को बनाने के दौरान बहुत अधिक माइक्रोप्लास्टिक्स (एमपी) का उपयोग किया जाता है। शोध में यह भी पता चला है कि गर्मी और माइक्रोप्लास्टिक निकलने के बीच एक मजबूत संबंध होता है, जैसे कि गर्म पानी आदि से बोतलों को साफ या स्टरलाइज़ करने के दौरान भी बहुत अधिक मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक निकलता है। इस शोध में एसएफआई रिसर्च सेंटर फॉर एडवांस्ड

मटेरियल एंड बायोइंजीनियरिंग रिसर्च, डबलिन के ट्रिनिटीहॉस और ट्रिनिटी कॉलेज इंजीनियरिंग और रसायन विज्ञान के स्कूलों से जुड़े शोधकर्ता हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि बच्चों को दूध पिलाने वाली प्लास्टिक की बोतलों को इस तरह से बनाया जाए, ताकि उनसे माइक्रोप्लास्टिक न के बराबर निकले, उन्होंने इसके लिए उपाय भी सुझाए हैं। यह शोध जर्नल नेचर फ़ूड में प्रकाशित हुआ है।

ट्रिनिटी की अगुवाई में इस शोध को डॉ. जिंग जिंग वांग, प्रोफेसर जॉन बोलैंड और प्रोफेसर लिवेन ज़ियाओ द्वारा किया गया है। टीम ने अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पालन करते हुए बच्चों को दूध पिलाने वाली पॉलीप्रोपाइलीन बोतल बनाने की विधि तैयार करने के दौरान माइक्रोप्लास्टिक के निकलने की क्षमता का विश्लेषण किया। उन्होंने 48 देशों और क्षेत्रों के 12 महीने के शिशुओं का माइक्रोप्लास्टिक से संपर्क का भी अनुमान लगाया है। जिसके निष्कर्ष निम्नलिखित हैं-

पॉलीप्रोपाइलीन-बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतल में 1.6 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक के कण और प्रति लीटर छोटे नैनोप्लास्टिक के खरबों कण निकल सकते हैं। स्टरलाइज़ करते समय जब पानी का तापमान 25 से 95 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, तो 6 लाख से 5.5 करोड़ प्रति लीटर तक माइक्रोप्लास्टिक के निकलने में वृद्धि होती है

अन्य पॉलीप्रोपाइलीन प्लास्टिक से बने उत्पाद (केटल्स, लंचबॉक्स) से भी माइक्रोप्लास्टिक के समान संख्या में कण निकलते हैं टीम ने दुनिया भर में सर्वेक्षण किया और 48 क्षेत्रों में 12 महीने के शिशुओं के माइक्रोप्लास्टिक्स के संपर्क का अनुमान लगाया। बच्चों की दूध पिलाने वाली बोतल बनाने तथा स्टरलाइज़ करने के वर्तमान दिशा-निर्देशों के बाद भी बच्चों का दैनिक औसत जोखिम स्तर 10 लाख से अधिक माइक्रोप्लास्टिक का है।

पॉलीप्रोपाइलीन-बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतलों से निकलने वाली माइक्रोप्लास्टिक का स्तर स्टरलाइज़ करने के तरीके और बोतल बनाने की प्रक्रियाओं का पालन करके काफी कम किया जा सकता है।

रांची मेयर आशा लकड़ा, ने "मेरी सहेली" और "नन्हे फरिश्ते" की सराहना की

रांची : मेयर आशा लकड़ा, रांची रेलवे स्टेशन पर आयीं और "मेरी सहेली" व "नन्हे फरिश्ते" टीम में पदस्थ अधिकारियों व जवानों से मिलीं तथा उनके कार्यों के क्रियान्वयन को देखा और दोनों टीमों की अत्यंत सराहना की।

रेलवे सुरक्षा बल, रांची मंडल द्वारा चलाए जा रहे दो महत्वूर्ण अभियान जिनमें से एक "मेरी सहेली" जिसके अंतर्गत रेलवे में यात्रा कर रही महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करना व सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना हैं। साथ ही साथ दूसरा अभियान जिसके अंतर्गत घर से भूले बिछड़े बच्चे जो कि रेलवे क्षेत्र में आ जाते हैं, तथा कुछ बच्चों को मानव तस्कर बहला फुसला कर रेल के द्वारा तस्करी के लिए ले जाने कि कोशिश करते हैं, ऐसे बच्चों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाकर उनके परिवार वालों को सुपुर्द करने व तस्करों पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।

इस अवसर पर रांची मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) एम एम पंडित, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवनीश तथा मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रशांत यादव मौजूद थे।

शारदा फाउंडेशन ने एकदिवसीयवुडबॉल कंडीशनिंग कैम्प का किया आयोजन

संवाददाता रांची :रविवार को सामाजिक संस्था शारदा फाउंडेशन एवं राँची जिला वुडबॉल संघ के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय वुडबॉल कंडीशनिंग कैम्प का आयोजन कांके रोड स्थित गाँधीनगर में आयोजित किया गया। जिसका उद्घाटन समाजसेवी राजीव रंजन एवं अशुतोष द्विवेदी ने संयुक्त रूप से स्ट्रोक लगाकर किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से वुडबॉल के कोच सह टेक्निकल गोविंद झा के मार्गदर्शन पर राष्ट्रीय खिलाड़ी देवपूजन ठाकुर ने खिलाड़ियों को वुडबॉल खेल की बारीकियों के गुर सीखाया साथ ही साथ वुडबॉल के विभिन्न प्रकार के स्ट्रोक के बारे में भी खिलाड़ियों को अवगत कराया।

कोविड19 के अनुसार पिछले 08 महीनों से खेल और खिलाड़ी दोनों प्रभावित हुए हैं। जिससे खिलाड़ियों के प्रैक्टिस पर काफ़ी अशर पड़ा है। इसी उद्देश्य से सामाजिक संस्था शारदा फाउंडेशन कि ओर से इस कैम्प का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के कोविड 19 गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रशिक्षण शिविर में 2 गज की दूरी का भी अनुपालन भी किया गया।

इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों को समाजसेवी राजीव रंजन एवं अशुतोष द्विवेदी ने परस्ती पत्र देकर सम्मानित किया इस अवसर पर देवपूजन ठाकुर,सईद अल्फराण,अंकित कुजूर,शिवम श्रीवास्तव, शुभम शर्मा,आदित्य पोद्दार, राजू गोप आदि खिलाड़ी उपस्थित थे। यह जानकारी खेल प्रशिक्षक गोविंद झा ने दी।

अब कैसे कहेंगे कि जुगनू हैं या जमीं पर उतरे हुये हैं तारे ?

चन्द्रिमा देवी

मौसम के बदलाव का संकेत देने वाले जुगनू जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खत्म होते जा रहे हैं

मसूरी के लंडोर में रहते हुए मुझे दो साल से अधिक हो गए हैं लेकिन मैंने कभी जुगनुओं को नहीं देखा था। स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने भी पिछले दो दशकों से जुगनू नहीं देखे। दुनियाभर में जुगनुओं के गायब होने का जो ट्रेंड देखा जा रहा है, लंडोर भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य उस वक्त हुआ जब इस साल जुलाई-अगस्त के महीने में ये चमकदार कीट लंडोर में अचानक नजर आए। ये जुगनू वुडस्टॉक स्कूल के आसपास चीड़ और ओक के जंगलों में शाम छह से सात बजे के आसपास देखे गए। आधी रात के बाद चिनार के पेड़ों पर भी इन्हें देखा गया। यह देखकर जुगनुओं के प्रति मेरी उत्सुकता बढ़ गई।

जुगनू विचित्र कीट हैं क्योंकि इनके पेट में रोशनी उत्पन्न करने वाला अंग होता है। ये विशेष कोशिकाओं से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और इसे लूसीफेरिन नामक तत्व से मिला देते हैं। इससे रोशनी उत्पन्न होती है और इस रोशनी में गर्मी न के बराबर होती है। इस प्रकार उत्पन्न होने वाली रोशनी को बायोल्यूमिनिसेंस कहा जाता है। दुनियाभर में मौजूद कीटों की प्रजाति में जुगनुओं की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है।अमेरिका के पेनिनसिलवेनिया स्थित बकनेल विश्वविद्यालय में एवोल्यूशनरी जेनेटिसिस्ट सारा लोवर के अनुसार, जुगनू कोलियोप्टेरा समूह के लैंपिरिडी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यह हमारे ग्रह पर डायनासोर युग से हैं। दुनियाभर में जुगनुओं की 2,000 से अधिक प्रजातियां हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में ये मौजूद हैं। भारत के अलग-अलग हिस्सों में इन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है। इन्हें हिंदी में जुगनू, बंगाली में जोनाकी पोका और असमिया में जोनाकी पोरुआ कहा जाता है। रात में निकलने वाले इन कीटों के पंख होते हैं जो इन्हें परिवार के अन्य चमकने वाले कीटों से जुदा करते हैं।

जुगनुओं का व्यवहार बताता है कि उनकी हर चमक का पैटर्न ''साथी'' को तलाशने का प्रकाशीय संकेत होता है। लेकिन जब छिपकली जैसे जीवों का उन पर हमला होता है तो वे रक्त की बूंदें उत्पन्न करते हैं जो जहरीले रसायन से युक्त होती हैं। जुगनू मुख्य रूप से पराग या मकरंद के सहारे जीवित रहते हैं और बहुत से पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जुगनुओं की उपयोगिता इस हद तक है कि वैज्ञानिक उनके चमकने के गुण की मदद से कैंसर और अन्य बीमारियों का पता लगा रहे हैं। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड के रिसर्चरों ने जुगनुओं को चमकने में मदद करने वाला प्रोटीन लिया और उसे एक केमिकल में मिलाया। जब उसे ट्यूमर कोशिका जैसे दूसरे मॉलेक्यूलर से जोड़ा गया तो यह चमक उठा। यह अध्ययन 2015 में नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित हुआ था।

जुगनू स्वस्थ पर्यावरण का भी संकेत देते हैं। ये बदलते पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और केवल स्वस्थ वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं। जुगनू वहीं रह पाते हैं, जहां पानी जहरीले रसायनों से मुक्त होता है, भूमि जीवन के विभिन्न चरणों में मददगार होती है और प्रकाश प्रदूषण न्यूनतम होता है।

बुझती रोशनी

अमेरिकी एरिक ली मेडर बताती हैं, ''सभी जुगनुओं की संख्या घटने की बात कर रहे हैं।'' देहरादून स्थित वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में वरिष्ठ वैज्ञानिक वीपी उनियाल कहते हैं, ''मैंने डब्ल्यूआईआई के परिसर में जुगनुओं की आबादी को तेजी से घटते हुए देखा है।'' हालांकि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि आबादी कितनी घटी है लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनकी संख्या सिकुड़ रही है और बहुत से स्थानों से जुगनू गायब हो चुके हैं। यह भी हो सकता है कि वे ऐसे स्थानों पर चले गए हों जहां उनके रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां जैसे नमी और आर्द्रता हो।

जुगनुओं की आबादी कई कारणों से कम हो रही है। इनमें पेड़ों की कटाई और बढ़ते शहरीकरण को भी प्रमुख रूप से शामिल किया जा सकता है। प्रकाश प्रदूषण के कारण भी जुगनू एक-दूसरे का प्रकाश नहीं देख पाते। इससे अप्रत्यक्ष रूप से उनका जैविक चक्र प्रभावित होता है क्योंकि ऐसी स्थिति में वे अपना साथी नहीं खोज पाते। ईकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में 2018 में प्रकाशित अध्ययन बताता है कि प्रकाश के कारण जुगनू रास्ता भटक जाते हैं, यहां तक की वे इससे अंधे तक हो सकते हैं। कीटनाशकों ने भी जुगनुओं के सामने संकट खड़ा किया है। जुगनू अपने जीवन का बड़ा हिस्सा लार्वा के रूप में जमीन, जमीन के नीचे या पानी में बिताते हैं। यहां उन्हें कीटनाशकों का खतरा रहता है।

जलवायु संकट : जुगनू बदलती जलवायु का भी संकेत देते हैं। बहुत- सी रिपोर्ट्स बताती हैं कि वैश्विक स्तर पर जलवायु की स्थितियां बदलने पर जुगनुओं का प्राकृतिक आवास और उनका फैलाव भी बदल रहा है। लंडोर में उनके प्रकट होने का यह एक कारण हो सकता है। जहां जुगनुओं ने अपने रहने का समय बढ़ा लिया है। यहां गर्मियां अधिक गर्म हो रही हैं। साथ ही अप्रैल से सितंबर के बीच एक्सट्रीम बारिश भी पड़ रही है। हो सकता है कि जलवायु की बदली परिस्थितियों में उन्होंने निचले हिमालय के इस क्षेत्र में प्रवास और अपने रहने का समय बढ़ा लिया हो। वर्ष 2016 में साइंस में प्रकाशित एक 12 वर्षीय अध्ययन बताता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वसंत ऋतु के गर्म होने से जुगनुओं का पीक समय पहले आ जाता है लेकिन यह तभी संभव है जब बारिश पहले जैसी रहे। उत्तरपूर्वी अमेरिका में स्थित कोरनेल विश्वविद्यालय में कीटविज्ञान के एमेरिटस प्रोफेसर माइकल हॉफमैन कहते हैं कि अन्य स्थानों पर जुगनुओं की बढ़ी हुई संख्या दिखने का कारण वसंत में नमी भी हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण अमेरिका के उत्तरपूर्वी हिस्सों में यह चलन देखा जा रहा है।

मैंने ऐसे बहुत से अध्ययन पढ़े हैं जो जुगनुओं की बायोलॉजी और उनके चमकने के गुण पर केंद्रित हैं। जुगनुओं की ईकोलॉजी और आवास पर जलवायु परिवर्तन का क्या असर पड़ा है, यह बताने वाले शोध बहुत कम हुए हैं। जुगनू ऐसे समय में गायब हो रहे हैं जब दुनियाभर में पतंगों की आबादी कम हो रही है। इससे जहां एक तरफ दुनियाभर में परागण में कमी का खतरा मंडराएगा और वहीं दूसरी तरफ फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की संख्या में इजाफा हो जाएगा।

(लेखिका वानिकी में डॉक्टरेट एवं स्वतंत्र शोधार्थी हैं)

हवा शुद्ध हो तो से प्लास्टिक कचरा भी कम होगा

दीपावली के पहले से ही वायु प्रदूषण पर देशव्यापी शोर हो रहा है। दिल्ली के आस पास पराली जलान का शोर तो दीपावली में पटाखों के चलाने से वायु प्रदूषण होने का शोर, पर कमाल की बात है कि देशव्यापी बहस के बावजूद इन पर रोक लगाने का किसी ने भी कोई ठोस प्रयास नहीं किया। हां हर साल की तरह इस पर राजनीति और बहस जम कर होती रही है।

अगर हम गौर से देखें तो कोविड संकट ने हमें एक मौका भी दिया है कि हम इसी के भय से संयम से रहें और उस प्रत्येक कृत्य से दूर रहें जो हर साल प्रदूषण का बड़ा कारण बनते हैं। कई मौकों पर हमने अपने पर्व त्यौहारों में संयम रखा और प्रदूषक वाले आयोजनों को कम किया, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है। सिर्फ चिंता करने, बहज और राजनीति करने से देश की हवा शुद्ध नहीं होगी।

एक शोध में कार्यालय कर्मियों द्वारा भोजन की 3,000 से अधिक तस्वीरें प्रस्तुत की गईं, जिसने एनयूएस टीम को यह तय करने में मदद की कि दोपहर के भोजन के विकल्पों में कितना अलग-अलग तरह का प्लास्टिक उपयोग होता है। विशेष रूप से, रेस्तरां में खाया जाने वाला भोजन बनाम कार्यालय में दिया जाने वाला भोजन। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि 100 ग्राम प्रति घन मीटर पीएम 2.5 वृद्धि ने भोजन के डिस्पोजेबल प्लास्टिक उपयोग को औसतन 10 ग्राम बढ़ा दिया था। एक प्लास्टिक कंटेनर के द्रव्यमान का लगभग एक तिहाई। अध्ययन में पता चला कि औसत वितरित भोजन में, एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक की वस्तुओं में लगभग 54 ग्राम प्लास्टिक का उपयोग किया गया था।

ऑर्डर बुक के आधार पर, शोधकर्ताओं ने यह भी अनुमान लगाया कि एक निश्चित दिन में, यदि चीन में 100 ग्राम प्रति घन मीटर पीएम 2.5 बढ़ जाता है, तो बीजिंग में 25 लाख अधिक भोजन के डिब्बे वितरित किए जाएंगे, अर्थात अतिरिक्त 25 लाख प्लास्टिक बैग और 25 लाख डिब्बे (प्लास्टिक कंटेनर) की आवश्यकता होगी।

अर्थशास्त्र विभाग के एसोच प्रोफेसर लियू ने कहा हमारे निष्कर्ष अन्य आम तौर पर प्रदूषित विकासशील देशों जैसे बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम पर भी लागू होते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन सही से नहीं किया जाता प्लास्टिक को लैंडफिल या नदियों में फैक दिया जाता है जो समुद्र तक पहुंच जाता है। हर साल 80 लाख टन प्लास्टिक के समुद्र में चले जाने का अनुमान है। हमारे अध्ययन से यह स्पष्ट है कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण से प्लास्टिक कचरे को कम किया जा सकता है। तो क्या हम सभी इसके लिये प्रयास भी करेंगे?

जलवायु सम्बन्धी मुक़दमे में फ़्रांसिसी अदालत ने लिया क्रन्तिकारी फ़ैसला

फ्रांस में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन संबंधी मुकदमे में, नीदरलैंड सरकार ने उत्सर्जन में कटौती के नए उपायों को अपनाने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। इस सहमति में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार कोयले के उपयोग में भारी कटौती भी शामिल है। अदालत का यह निर्णय हर लिहाज़ से महत्वपूर्ण है और फ्रांसीसी सरकार की जलवायु निष्क्रियता के सामने एक निर्णायक कदम है। अब फ्रांस के जलवायु उद्देश्य, और उन्हें प्राप्त करने की उसकी योजना, को अब कानूनी रूप से बाध्यकारी माना जायेगा। यह फ़ैसला आज फ्रांस की सर्वोच्च प्रशासनिक अदालत, कॉन्सिल डी'अटैट (काउंसिल ऑफ स्टेट), ने सुबह ग्रैंड-सिनटे (फ्रांस के उत्तर में) शहर के प्रशासन द्वारा एक कानूनी अपील पर सुनवाई के बाद सुनाया। इस मुक़दमे में सक्रिय रूप से शामिल चार गैर सरकारी संगठनों के अनुसार यह "केस ऑफ द सेंचुरी" है और कॉन्सिल डी'अटैट ने सरकार की पिछली जलवायु योजना की विश्वसनीयता पर न सिर्फ़ एक प्रश्नचिन्ह लगाया बल्कि इस योजना की जनता के आगे जवाबदेही भी तय करने और उसके मुल्यांकन पर ज़ोर दिया। यह चार ग़ैर सरकारी संगठन हैं- नोट्रे अफेयर ए टूस, फेनडेशन निकोलस हुलोट, ग्रीनपीस फ्रांस, और ऑक्सफैम फ्रांस।

"द कॉन्सिल डी'अटैट के फैसले ने न सिर्फ़ फ्रांस की जलवायु नीति को वापस पटल पर रख दिया बल्कि सरकार को उसकी जलवायु परिवर्तन रोकने की अपनी ज़िम्मेदारी से भी रूबरू कराया। यह ऐतिहासिक फ़ैसला एक लिहाज़ से क्रन्तिकारी है क्योंकि अब तक पर्यावरण से जुड़े कानून महज़ सरकारों और सांसदों के अस्पष्ट वादों के रूप में माने जाते रहे है। अब वक़्त है फ्रांसीसी सरकार का अपने कानूनी दायित्वों को निभाने का और जलवायु सम्बन्धी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस और प्रभावी उपायों को लागू करे का।

जी20 देश कुछ ऐसे निवेश कर रहे हैं!

एजेंसियां

कोविड-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिये जी20 देशों द्वारा इकोनॉमिक रिकवरी या आर्थिक पुनरुत्थान के नाम पर जम कर कोयले, तेल और गैस से सम्बन्धित परियोजनाओं में भारी निवेश किये जा रहे हैं और इससे पर्यावरण से, कोविड-पूर्व, मिलने वाले सकारात्मक रुझानों पर अब खतरा मंडराता नज़र आ रहा है। ये चुनिन्दा अर्थव्यवस्थाएं कोविड-19 रिकवरी पैकेज का एक बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधन से जुड़े उद्योगों में खर्च कर रही हैं, जिससे अगले 10 सालों में हरित ऊर्जा को सौ फ़ीसद अपनाने में अच्छी ख़ासी रुकावटें पैदा होंगी। ऐसा कहना है जी20 देशों के 14 थिंक टैंक के सालाना समझौते के तहत प्रकाशित 2020 क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का।

इस रिपोर्ट में तमाम महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गये हैं और अगर बात फ़िलहाल भारत की ही करें तो कोविड-19 महामारी ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक प्रकार की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से अवगत कराया। मई 2020 में, प्रधान मंत्री मोदी की USD 266bn कोविड19 - राहत पैकेज भारत की वार्षिक GDP का लगभग 10% था, लेकिन इसमें जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई पर्याप्त निवेश नहीं थे। अब आगे दिए जाने वाला स्टिमुल्स का पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिजली क्षेत्र, परिवहन और शहरी नियोजन में एनर्जी ट्रांजीशन को तेजी देना। इसके बिना, लॉकडाउन से उत्सर्जन में गिरावट की संभावना ग्रीन रिकवरी के बिना फिर से बढ़ेगी।

भारत का प्रति कैपिटा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, G20 के औसत से काफी नीचे है। पर भारत के उत्सर्जन में पिछले एक दशक में तेजी से वृद्धि हुई है और इसके और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने का अनुमान है। भारत विभिन्न नीतियों के माध्यम से कोयला पर टैक्स और सब्सिडी दोनों देता है। भारत विभिन्न राजकोषीय नीतियों के माध्यम से कोयला टैक्स और सब्सिडी दोनों देता है। कोयला को दी जाने वाली सब्सिडी, उसकी जगह रिन्यूएबिल्स को देने से लागत बचत हो सकती है, और हवा की गुणवत्ता में सुधार जैसे महत्वपूर्ण सह-लाभ भी होंगे। उसके पास वर्तमान में कोयले को चरणबद्ध रोप से ख़त्म करने की कोई योजना नहीं है। भारत को कोल फेज-आउट के लिए एक रोडमैप विकसित करने की सख्त ज़रूरत है। हालांकि ऐसा करने से कोयला खनन में लगे मजदूरों और समुदायों के साथ साथ थर्मल पॉवर में कम कर रहे लोगों की नौकरियों पर असर पड़ेगा और इस बात को ध्यान में रख कर बदलाव करना होगा।

भारत का परिवहन क्षेत्र वर्तमान में अपनी ऊर्जा संबंधित CO_2 उत्सर्जन के 14% के लिए जिम्मेदार, एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है जिसमे वाहन स्वामित्व तेज़ी से बढ़ रहा है, और सरकार को एश२ की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मजबूत कार्रवाई करने और 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहनों के अपने लक्ष्य को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि वैश्विक 1.5 °CIPCC परिदृश्यों के साथ संगत होने और अपनी सीमा के अंदर के लिए भारत को 2030 तक उत्सर्जन में वृद्धि को 4.597 मिलियन टन कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन) से कम करने और उसे 2050 तक 3.389 MtCO2e की सीमा में लाने की ज़रूरत है। भारत ने अपना 2030 राष्ट्रीय स्तर पर स्व-निर्धारित कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का लक्ष्य केवल 6,034 MtCO2e और 6,203 MtCO2e के बीच अपने उत्सर्जन को सीमित करना रखा है भारत एक वैश्विक नेता बन सकता है, अगर वह नए कोयले से चलने वाली बिजली बनाने की योजनाओं को छोड़ दे और 2040 तक बिजली के लिए कोयले के उपयोग को चरणबद्ध कर देता है। यह आंकड़े भूमि के उपयोग के उत्सर्जन को छोड कर पूर्व-कोविड-19 अनुमानों पर आधारित हैं। रिपोर्ट जी20 देशों के नेताओं को अपने यहां विभिन्न क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करने के लिये प्रेरणा तथा प्रोत्साहन देने के सिलसिले में व्यापक नजरिया उपलब्ध कराती है। इस रिपोर्ट में जलवायु अनुकूलन, प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन में कमी और वित्तपोषण के करीब 100 पैमानों पर जी20 देशों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी द्वारा की गयी छठी सालाना समीक्षा में कोविड-19 संकट को लेकर जी20 देशों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया और वर्ष 2020 के लिये उत्सर्जन सम्बन्धी ताजा डेटा और अनुमानों को समर्पित एक अतिरिक्त अध्याय भी शामिल है। पूरी दुनिया में ग्रीनहाउस गैसों के कुल उत्सर्जन में जी20 देशों की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत है।

वर्ष 2020 के संस्करण में जलवायु संरक्षण के मामले में जी20 देशों के प्रदर्शन का आकलन करने के साथ-साथ कोविड-19 संक ट के प्रभावों और उन्हें लेकर सरकारों द्वारा उठाये गये कदमों के विश्लेषण को भी शामिल किया गया है। वर्ष 2019 में ऊर्जा सम्बन्धी उत्सर्जन में वृद्धि के दीर्घकालिक रुख में उल्लेखनीय कमी आने के साथ-साथ जी20 देशों में अक्षय ऊर्जा का एक रफ्तार से विकास भी हुआ है। मगर, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की डॉक्टर शार्लीन वॉटसन कहती हैं, ''जी20 देशों के कम से कम 19 देशों ने अपने घरेलू तेल, कोयला तथा/अथवा गैस क्षेत्रों को वित्तीय सहयोग देने का फैसला किया है। इसके अलावा 14 देशों ने जलवायु संरक्षण सम्बन्धी शर्तें लगाये बगैर अपनी राष्ट्रीय विमानन कम्पनियों को वित्तीय मदद देने का निर्णय लिया है। सिर्फ 4 जी20 देशों ने ही जीवाश्म ईंधन से जुड़ी परियोजनाओं या प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के मुकाबले ग्रीन सेक्टरों को ज्यादा धन दिया है। रिकवरी पैकेज या तो जलवायु संकट का समाधान करते हैं, या फिर हालात को और भी खराब कर सकते हैं। जी20 देशों के कुछ सदस्य, जैसे कि यूरोपीय यूनियन, फ्रांस तथा जर्मनी जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों से खुद को बचाते हुए अधिक सतत अर्थव्यवस्था का निर्माण कर अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं। वहीं, अन्य देशजीवाश्म ईंधन को अत्यधिक समर्थन करके हाल में बने अच्छे माहौल को खराब करने का खतरा पैदा कर रहे हैं। आने वाले महीनों में राजनीतिक पसंद से यह तय होगा कि जी20 देश उत्सर्जन के ग्राफ को सतत रूप से झुकाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। हालांकि चीन, दक्षिण अफ्रीका, जापान और दक्षिण कोरिया इस सदी के मध्य तक कार्बन से मुक्ति पाने की दौड़ में हाल ही में शामिल हुए हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल मुल्कों में जलवायु सम्बन्धी मुश्किल लक्ष्यों को हासिल करने के लिये जरूरी रफ्तार बन रही है। हालांकि अल्पकालीन नीतियां और निवेश अब भी दीर्घकालिक योजनाओं के अनुरूप नहीं हैं। यह तब है जब वैश्विक तापमान में वृद्धि का आंकड़ा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है और परिणामस्वरूप तपिश, जंगलों की आग और बाढ़ जैसी जलवायु सम्बन्धी चरम स्थितियों के कारण जी20 देशों में हालात अपेक्षाकृत बदतर हो जाएंगे। वैश्विक तापमान में डेढ़ डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी की स्थिति में जी20 देशों में से ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, इटली, मेक्सिको, तुर्की, भारत, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका पर वैश्विक अनुमानों के मुकाबले कहीं ज्यादा बुरा असर पड़ने का खतरा है। इसमें महत्वपूर्ण अंतर की भी पहचान की गयी है कि कैसे सरकारें कार्बन से मुक्ति पाने की चुनौती पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। उदाहरण के तौर पर जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध ढंग से इस्तेमाल से बाहर करने की तिथियां तय कर चुके हैं। वहीं, ट्रम्प प्रशासन ने वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने सम्बन्धी नियम वापस ले लिये। जी20 में शामिल 18 देशों ने अपनी कार्बन प्राइसिंग योजनाओं को या तो लागू कर दिया है, या फिर ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी कोई योजना ही नहीं बनायी है।

कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन ने जहां कोयले के लिये सार्वजनिक वित्तपोषण पर जहां पूरी तरह पाबंदी लगा दी है, वहीं चीन, भारत, इंडोनेशिया, रूस तथा दक्षिण अफ्रीका ने ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं लगाये हैं। कैटरीना गोडिन्यो ने कहा ''हमें आगामी जी20 समिट और अगले साल होने वाली यूएन क्लाइमेट कांफ्रेंस में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों और सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले मुल्कों की बढ़ी हुई प्रतिबद्धताओं और नेतृत्व की फौरन जरूरत है।

जीवाश्म ईंधन को 2030 तक, ब्रिटेन कर देगा बे 'कार'!

अगले दस सालों में ही बिक पाएंगी नई पेट्रोल/डीज़ल कार, 2035 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के अनुरूप करने होंगे सभी निवेश और कारोबार

एक ताज़ा वैश्विक घटनाक्रम में यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने एक हरित औद्योगिक क्रांति के लिए प्रतिज्ञा ली है। उनके नेतृत्व में ली गयी इस प्रतिज्ञा का दावा है कि यूके में न सिर्फ़ ऊर्जा, परिवहन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 250,000 नौकरियों का सृजन होगा बल्कि 2030 तक वहां नयी डीजल और पेट्रोल करों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लग जायेगा।

साथ ही, उसके बाद अगले पाँच सालों में सभी नए निवेश, कारोबार, हीटिंग सिस्टम, और कारों को शून्य कार्बन उत्सर्जन के अनुरूप होना पड़ेगा। यहीं नहीं, 2021 तक ट्रेजरी को सभी निवेश निर्णयों की समीक्षा करनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी निवेश शुद्ध शून्य कार्बन के अनुसार हों। और सरकार की जलवायु अनुकूलन टीमों की सभी योजनाएं, विश्व तापमान वर्ष 2100 तक 4 को ध्यान मैं रखकर बनाना शुरू कर देना चाहिए। इसी क्रम में यह फ़ैसला भी लिया गया कि सभी तरह के व्यवसायों को 'नेट शून्य कार्बन के अनुसार निगरानी और सत्यापन' के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। इस बात की भी उम्मीद है कि यूके नए एनडीसी कंट्रीब्यूशन को दिसंबर 2020/जनवरी 2021 तक प्रस्तुत करेगा।

इस पूरे घटनाक्रम का आधार बनी यूके क्लाइमेट असेम्बली की एक जांच रिपोर्ट जो कहती है कि कोविड के बाद सरकार को सभी भागीदारों (चीन, अमेरिका सहित) के साथ काम करना चाहिए, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज जलवायु-अनुकूल हों। इस जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि.....

कुल 93% विधानसभा सदस्य पूरी तरह से सहमत थे कि नियोक्ताओं और अन्य लोगों को लॉकडाउन आसान करने के इस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे जीवन शैली में ऐसे बदलाव आएं कि वह नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के अनुरूप हो सकें।

* 79% सदस्यों को लगता था कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने में मदद के लिए सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए उठाए गए कदम ठीक हैं लेकिन 9% सदस्य इस बात से असहमत थे। इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट (क्क्रएऊ) की वरिष्ठ फेलो डॉ कमिला तौल्मिन कहती हैं, ''महामारी के कारण जलवायु सम्बन्धी वार्ताएं लगभग एक वर्ष पीछे चली गई हैं, उडढ26 के राष्ट्रपति के रूप में हम वर्ष 2020 में जलवायु कार्रवाई में मंदी या देरी को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते हैं। ब्रिटेन में और दुनिया भर में जलवायु का प्रभाव बार बार और लगातार महसूस किया जा रहा है। कई अफ्रीकी देश जलवायु प्रभावों और महामारी की दोहरी मार की वजह से एक गंभीर ऋण संकट का सामना कर रहे हैं। जलवायु संकट थम नहीं रहा है।''

यह रिपोर्ट और प्रधान मंत्री जॉनसन के फ़ैसले दर्शाते हैं कि युके रिकवरी पैकेज पेश करके अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है जिससे आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था, नौकरियों और जलवायु के अनुरूप कम कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा मिलेगा।

आगे, इंस्टीट्यूट फॉर न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग (क्ठएळ) के सीनियर फेलो, एडिअर टर्नर ने कहा, ''समिति उन नीतियों के लिए अधिक अवसर प्रदान करने पर जोर देती है जिससे दोनों दिशाओं में प्रगति होगी एक ओर आर्थिक सुधार और दूसरी ओर शून्य कार्बन उत्सर्जन, जो बिल्कुल सही भी है।

वो आगे कहते हैं, ''ब्याज की गिरती हुई दरों को देखते हुए, अब अक्षय ऊर्जा और हरित बुनियादी ढांचे के अन्य रूपों में निवेश करने का समय है; रोजगार को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए सरकार की नीतियां हरित रोजगार बनाने पर केंद्रित होनी चाहिए और उन फर्मों को सरकारी समर्थन मिलना चाहिए जो उत्सर्जन में कटौती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं, पुरानी तकनीक पर निर्भर और संभावित रूप से फंसी हुई परीसंपत्तियों का समर्थन करने से बचना चाहिए।''

एनर्जी एंड क्लाइमेट इंटेलिजेंस यूनिट (एउक्व) के विश्लेषक जेस राल्स्टन कहते हैं, "कुछ समय के लिए यह स्पष्ट है कि वङ का बिल्डिंग स्टॉक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के अनुसार नहीं है और महामारी के दौरान ये भी पता लगा कि हमारे घर पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। फिर भी आज, उउउ की रिपोर्ट वास्तव में इस बात पर प्रकाश डालती है कि हमें इस उद्देश्य को पाने के लिए और कदम उठाने होंगे - क्योंकि यूके के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रति मिनट एक से अधिक घर 2050 तक रेट्रोफिट किए जाने की आवश्यकता होगी।

एक महत्वपूर्ण बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, ''इस सब के साथ ही साथ एक पेचीदा सेक्टर को ्रीं१ङ्क्षब्ल्ठरी करने के लिए, घरों को एनर्जी एफ्फिसियेंट बनाने और साथ ही साथ ऊर्जा बिल कम करने से देश भर में, अच्छी सैलरी और कुशल नौकरियों को भी अनलॉक किया जा सकता है, जिन क्षेत्रों में घरों में एनर्जी एफिसिएंसी ठीक नहीं है, खासकर उत्तर और मिडलैंड्स के इलाकों में, वहां स्टॉक को रेट्रोफिट कर अधिक नौकरियों के अवसर पैदा किये जाने चाहिए, जिससे सरकार को कानूनी रूप से आवश्यक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक वास्तविक अवसर पैदा हो सके।

द्वारा : क्लाइमेट कहानी

वायु प्रदूषण से हर तीन मिनट में एक बच्चे की मौत, राजस्थान सबसे ऊपर

एक अध्ययन में बताया गया है कि देश में प्रति तीन मिनट एक बच्चा अपने निचले फेफड़े के संक्रमण(एलआरआई) के कारण मौत के मुंह में जा रहा है। इस संक्रमण का सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण बताया गया है

क्या आप जानते हैं कि देश के नौनिहालों के लिए वायु प्रदूषण कितना बड़ा साइलेंट किलर बन गया है? वायु प्रदूषण से भारत में हर तीन मिनट में एक बच्चे (0 से 5 साल) की मौत हो जाती है। 2017 में भारत में वायु प्रदूषण से लगातार एक लाख 85 हजार से अधिक बच्चों की मौत हो गई। यानी, औसतन रोजाना का आकलन किया जाए तो रोजाना लगभग 508 बच्चों की मौतें हुई। ये आंकड़े ग्लोबल बर्डेन डिजीज, 2017 (पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, भारतीय अनुसंधान चिकित्सा परिषद, आईएचएमई के संयुक्त अध्ययन) के अध्ययन में सामने आए हैं।

अध्ययन में यह बताया गया है कि देश में प्रति मिनट एक बच्चा अपने निचले फेफड़े के संक्रमण(एलआरआई) के कारण मौत के मुंह में जा रहा है। इस संक्रमण का सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण बताया गया है।

यदि पूरे देश के राज्यों को देखें तो इस बीमारी से राजस्थान देश में सबसे ऊपर है। जहां एक वर्ष में 126 बच्चे मर जाते हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। यहां 112 मौतें हो जाती हैं।

निजि वाहनों पर अंकुश जरूरी

भारत में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के लिए काफी हद तक वाहन जिम्मेवार हैं। अकेले दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो यहां रोजाना लगभग 4 करोड़ यात्राएं होती हैं। इनमें से मात्र 10 से 20 फीसदी यात्राएं सार्वजनिक परिवहन से की जाती हैं। ऐसे में, यदि निजी वाहनों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं।

सेंटर फार साइंस एंड एनवॉयरमेंट की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रायचौधरी कहती हैं कि दिल्ली-एनसीआर में 4 करोड़ यात्राओं में से 30 से 35 लाख मेट्रो और करीब 30 लाख यात्राएं ही अन्य सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं। करीब 3.5 करोड़ यात्राएं रोजाना निजी वाहनों से हो रही हैं। ऐसे में इसका बोझ सीधा ऊर्जा, पर्यावरण, समय और लोगों की जिदंगियों पर है। कोशिश होनी चाहिए कि 3.5 करोड़ यात्राएं भी सार्वजनिक परिवहन के जरिए की जाएं। अभी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली दौड़ती है।

सायकिल से डर नहीं लगता साहब, ट्रैफिक से लगता है!

बात गाड़ियों के धुंए से पर्यावरण बचाने की हो तो सबसे पहला ख्याल साईकिल का आता है। लेकिन साईकिल चलायें भी तो भला कैसे? एक तरफ तेज़ रफ्तार गाड़ियों की चपेट में आने का डर तो दूसरी तरफ गड्ढों और नालियों में गिर कर चोटिल होने की आशंका - कुल मिलाकर भारत में हालात कतई आसान नहीं सायकलिंग के लिए। ऐसा मानना है भारत की जनता का, अगर एक ताज़ा सर्वे की मानें तो...

दरअसल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी द्वारा आवास और शहरी वायु मंत्रालय द्वारा इस सर्वेक्षण का आयोजन चैलेंज के हिस्से के रूप में किया गया। पचास शहरों में किए गए इस सर्वेक्षण में पाया गया कि ट्रैफिक की चपेट में आने या ख़राब सड़क की भेंट चढ़ने के साथ 20 प्रतिशत महिलाएं इस वजह से सायकिल नहीं चलाती क्योंकि उन्हें किसी प्रकार की छेड़खानी की आशंका सताती है। सर्वे में लगभग 50,000 लोगों को सम्पर्क किया गया यह जानने के लिए कि आखिर वो क्या वजहें हैं जो किसी को सायकिल चलाने से रोकती हैं और इस सब के बीच जो लोग सायकिल चला रहे हैं वो किन वजहों से चला रहे हैं। और जवाब में अधिकांश उत्तरदाताओं ने कहा कि अगर साइकिल चलाना सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाता है तो उन्हें काम, शिक्षा, और मनोरंजन के लिए साइकिल चलाने से कोई ऐतराज़ नहीं। उत्तरदाताओं ने साइकिल पार्किंग की कमी, सड़क पर गाड़ियों की बेतरतीब पार्किंग, और खराब स्ट्रीट-लाइटिंग जैसे मुद्दों को भी इंगित किया। लगभग 52% पुरुषों और 49% महिलाओं ने मुख्य सड़कों पर साइकिल चलाना असुरक्षित पाया, जबकि 36% पुरुषों और 34% महिलाओं ने चौराहों पर साइकिल चलाने में डर की बात की।

सर्वे के नतीजों के मुताबिक़ जो लोग साइकिल चलाना जानते हैं, उनमें से केवल एक चौथाई लोग ही इसे रोज़ाना चलाते हैं और लगभग आधे हफ्ते में कुछ दिन साइकिल चलाते हैं। सर्वे पर प्रतिक्रिया देते हुए कोहिमा स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड में प्रौद्योगिकी अधिकारी अटूबा लांगकुमेर, कहते हैं,

''हम वो सब कर रहे हैं जिससे कोहिमा के लोग सायकिल चलाने को प्रेरित हों। हमें अच्छे नतीजे भी मिल रहे हैं। अब हमें उम्मीद है कि कोहिमा इस दिशा में एक मिसाल बन कर उभरेगा। सर्वेक्षण के ज़रिये 28 शहरों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर साइकिल चलाने में आने वाली बाधाओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। इस क्रम में पूरे देश में 340 किमी से अधिक लम्बाई के सायकलिंग गलियारे (कॉरिडोर) और 210 वर्ग किलोमीटर के आस पड़ोस(नेबरहुड) के क्षेत्रों को चुना गया हैं। भागीदारी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, राजकोट, कोहिमा, और मंगलुरु सहित 28 शहरों ने जमीनी स्तर पर बाधाओं का आकलन करने के लिए एक 'हैंडलबार सर्वेक्षण' किया और अब पायलट प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन समाधान शुरू कर दिए गए हैं।

इंडिया साइकल्स4चेंज चैलेंज एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य साइकिल के अनुकूल शहरों का निर्माण करना है और इसमें सर्वेक्षण नागरिक-नेतृत्व वाले दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख घटकों में से एक है। शहरों ने तमिल, मराठी और कन्नड़ जैसी स्थानीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी और हिंदी में सर्वेक्षण किया।

भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव, कुनाल कुमार इस सर्वे का महत्व और प्रासंगिकता समझाते हुए कहते हैं, इंडिया साइकल्स4चेंज चैलेंज यह सुनिश्चित कर रहा है कि लोग योजना प्रक्रिया के केंद्र में हों। मैं नागरिकों से इसमें भाग लेने, समर्थन दिखाने और अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए आग्रह करता हूं।

अस्पतालों को 31 दिसंबर लगाना होगा ईटीपी

पंजाब के अमृतसर जिले में कुल 862 स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (एचसीएफ) हैं। 862 एचसीएफ में से 367 एचसीएफ में बिस्तरों (बेड) की सुविधा हैं और शेष 495 एचसीएफ में केवल देखभाल की सुविधा हैं। लगभग 853 एचसीएफ ने जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत पूरे जीवनकाल में कम से कम एक बार अनुमतियां और सहमति प्राप्त की है और शेष 9 एचसीएफ ने उक्त नियमों के तहत पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की है। 9 एचसीएफ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

367 बिस्तरों वाले अस्पतालों में से, 55 बिस्तरों वाले अस्पतालों ने अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) लगाए हैं। शेष 312 बिस्तरों वाले अस्पतालों को 31 दिसंबर, 2020 तक ईटीपी लगाना आवश्यक है।

मप्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अव्वल

मध्य प्रदेश द्वारा अपनाया गया क्लस्टर आधारित एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल 7 समूहों और विभिन्न चरणों में काम कर रहा है। इसमें कुल 110 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) शामिल हैं। इन 7 समूहों में से 4 क्लस्टर कचरे को खाद (सागर, कटनी, छतरपुर और सिंगरौली) में और 3 क्लस्टर (जबलपुर, रीवा और ग्वालियर) में अपशिष्ट से ऊर्जा बना रहे हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विशेषज्ञों के साथ विभिन्न विकल्पों की समीक्षा और चर्चा की, शेष में मिश्रित मॉडल दृष्टिकोण को अपनाने पर पुनर्विचार किया जा रहा है। 'एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' (आईएसडब्ल्यूएम) परियोजनाओं के साथ क्लस्टर आधारित 'विकेन्द्रीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' (एसडब्ल्यूएम) को 268 शहरी स्थानीय निकायों में अपनाया जा रहा है।

गन्ने की फसल हुई बर्बाद

उत्तर प्रदेश में लगभग 40 हजार हेक्टेयर में खड़े गन्ने को हुआ कैंसर रेड रॉट (लाल सड़न) रोग के कारण उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गन्ने की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गांव लोनी में रेड रॉट बीमारी के कारण गन्ने की फसल सूख गई है। फोटोः राजू सजवानउत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गांव लोनी में रेड रॉट बीमारी के कारण गन्ने की फसल सूख गई है।

मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र, धूर्वा में मना विश्व मत्स्य दिवस

21 नवबंर को पूरे विश्व में विश्व मात्सियकी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र धुर्वा, रांची में एक कार्यक्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर अबु बकर सिद्दिकी सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता , झारखंड रांची की अध्यक्षता में आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना विषय पर एक संगोष्ठि का आयोजन किया गया।इस अवसर पर मत्स्य पालन प्रसंस्करण एवं विपणन के विभिन्न आयामों जैसे मछली प्रजनन, बीज उत्पादन, मछली पालन, मछली की शिकारगाही, केज कल्चर, पेन कल्चर, मछी की बिक्री, रंगीन मछलियों का पालन इत्यादि कई माध्यमों से रोजगार का सृजन करने के विषय पर चर्चा की गयी। साथ ही इनसे संबंधित सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर अबु अकर सिद्दिक ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि कोविड 19 के समय में भी राज्य में मछली का उत्पादन 1.23 लाख मे. टन हुआ है।

इस अवसर पर डॉ. द्वीवेदी निदेशक मत्स्य, मनोज कुमार संयुक्त मत्स्य निदेशक, मनोज कुमार सहायक मत्स्य निदेशक, शंभू प्रसाद यादव, अशेक कुमार सिंह, श्रीमति नीलम सरोज एक्का,धनराज आर कापसे, श्रीमति स्वर्णलता मधु लकड़ा, श्रीमति रेवती हांसदा व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

कोल इंडिया अध्यक्ष ने सीसीएल के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की

रांची : 21 नवम्बर को सी.सी.एल. मुख्यालय, दरभंगा हाउस, रांची में कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने सी.सी.एल. के कार्य निष्पादन की समीक्षा बैठक किया। बैठक में सीसीएल के सीएमडी पी.एम. प्रसाद, निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त) एन.के. अग्रवाल, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) भोला सिंह, महाप्रबंधक/चेयरमैन, कोल इंडिया के तकनीकी सचिव एम.के. सिंह, सीएमडी के तकनीकी सचिव एम.वी. रजिमवाले सहित सीसीएल मुख्यालय के विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये उपस्थित थे।

कोल इंडिया अध्यक्ष का सीसीएल दौरा

सीसीएल के सीएमडी पी.एम. प्रसाद ने अध्यक्ष, कोल इंडिया प्रमोद अग्रवाल का स्वागत किया। बैठक के दौरान प्रसाद ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कंपनी के कोयला उत्पादन, एमडीओ (माईन डेवलपर एंड ऑपरेटर) मोड संबंधित प्रोजेक्ट, भूमि अधिग्रहण, नये वाशरी आदि विषय पर विस्तार से जानकारी दी। समीक्षा बैठक में प्रमोद अग्रवाल ने उपस्थित सभी महा प्रबंधक/विभागाध्यक्ष को प्रेरित करते हुये आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जिससे कंपनी अपने कोयला उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अग्रवाल ने परियोजना विस्तारिकरण, नये परियोजाओं के उत्पादन क्षमता आदि पर विस्तार से चर्चा किया।

सीएमडी प्रसाद ने कहा कि सीसीएल अपने लक्ष्य की ओर सतत अग्रसर है। उन्होंने सभी क्षेत्रों के कोयला उत्पादन एवं अन्य बिन्दुओं पर अध्यक्ष, कोल इंडिया को अवगत कराया। सीएमडी ने कहा कि सरकार, स्थानीय लोगों एवं सभी स्टेकहोल्डर्स का सहयोग कंपनी को मिलता आ रहा है। इससे पूर्व 20 नवम्बर को अध्यक्ष, कोल इंडिया प्रमोद अग्रवाल ने आम्रपाली-चन्द्रगुप्त, मगध-संघमित्रा का दौरा किया। उन्होंने कोयला उत्पादन, प्रेषण, खदान विस्तार, पर्यावरण मंजूरी एवं भूमि संबंधित मुद्दो पर विस्तार से जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिया। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर सीएमडी पी.एम. प्रसाद सहित निदेशकगण, महाप्रबंधक (आम्रपाली-चन्द्रगुप्त)ए.के. चौबे, महाप्रबंधक (मगध-संघमित्रा) के.के. सिन्हा एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। यह जानकारी सीसीएल के विभागाध्यक्ष (जनसम्पर्क) अनुपम कुमार राणा ने दी।

ऑनलाइन ड्राइंग प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया

रेल सुरक्षा बल, रांची रेल मंडल द्वारा रेल सुरक्षा बल के 36वें स्थापना दिवस (रेजिंग डे) समारोह के उपलक्ष में रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों के बच्चों के लिए ऑनलाइन ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जिसमें बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को दिनांक 18/11/2020 को मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रशांत यादव द्वारा मंडल कार्यालय के सभाकक्ष में पुरस्कृत किया तथा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी, साथ ही बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को मुख्यालय के फोटो गैलरी तथा आरपीएफ पोस्टों के फोटो गैलरी में लगाने का निर्देश भी दिया।

औद्योगिक गतिविधियों के कारण कोसी नदी में प्रदूषण

प्रतीकात्मक फोटो

19 नवंबर, 2020 को न्यायमूर्ति एसवीएस राठौर की अध्यक्षता वाली निरीक्षण समिति ने सिफारिश की कि भूजल को उपयोग में लाने वाली सभी इकाइयों के संयंत्रों को होने वाली पानी की वास्तविक आवश्यकता का आकलन कर पानी के ऑडिट कराने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए जिसमें सतही जल जैसे स्रोत, उपचारित जल का पुनः उपयोग या जल संचयन आदि शामिल हैं। ऐसे सभी उद्योगों को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपचारित पानी का उपयोग करने के तरीकों का पता लगाने के लिए नगरपालिका निकायों के साथ चर्चा करनी चाहिए। एक ऐसी योजना जिसमें पानी की न्यूनतम बर्बादी हो, इसे तैयार किया जाना चाहिए और इसे लागू किया जाना चाहिए।

उद्योगों को पीने और उपयोग के लिए पानी को उपयुक्त बनाने के लिए तृतीयक जल उपचार सुविधाओं को लगाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। भूजल के गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में, बोरवेल ऐसी सभी इकाइयों के आसपास खोदे जा सकते हैं और पानी के नमूनों को समय-समय पर केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) / राज्य भूजल प्राधिकरण (एसजीडब्ल्यूए) द्वारा हर तरह के के प्रदूषण का विश्लेषण किया जाना चाहिए। औद्योगिक गतिविधियों के कारण रामपुर जिले के कोसी नदी में होने वाले प्रदूषण का मुद्दा विचारणीय था। मुरादाबाद में भेल नदी, रामपुर में कोसी नदी की एक सहायक नदी है जो रामगंगा की सहायक नदी है जो बदले में गंगा नदी की सहायक नदी है।

हालांकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में स्थित उद्योगों द्वारा इन नदियों में प्रदूषण होता है, लेकिन निरीक्षण समिति ने केवल उत्तर प्रदेश में स्थित इकाइयों पर विचार किया क्योंकि उत्तराखंड के लिए एक अलग निरीक्षण समिति है।

रीवा में अवैध खनन नहीं हो रहा है

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) द्वारा सौंपी गई संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, रीवा जिले के तहसील हुजूर ग्राम बैजनाथ में कोई अवैध खनन गतिविधि नहीं देखी गई।

यह तहसील हुजूर के ग्राम बैजनाथ, हिनौटी और खमरिया के क्षेत्र में अवैध खनन से जुड़ा मामला है।

रिपोर्ट में कहा गया कि ग्राम बैजनाथ में रीवा जिले के खनन कार्यालय द्वारा 80 पत्थर खदान पट्टे स्वीकृत किए हैं। क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधि के संबंध में रीवा के खनन अधिकारी ने बताया कि जिला कलेक्टर ने ग्राम बैजनाथ और आस-पास के क्षेत्र में अवैध खनन और उसकी ढुलाई पर नियंत्रण के लिए निरंतर सतर्कता रखने के लिए एक समिति का गठन किया था। खनन विभाग की समिति ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के अनुसार क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके अलावा 23 अक्टूबर को जिला कलेक्टर को सौंपी गई समिति की रिपोर्ट के अनुसार, रीवा और उसके आस-पास के क्षेत्र में कोई अवैध खनन गतिविधि नहीं देखी गई। एमपीपीसीबी समिति ने 5 नवंबर को ग्राम बैजनाथ और उसके आसपास के क्षेत्र का भी दौरा किया और निरीक्षण के समय क्षेत्र में कोई भी अवैध खनन गतिविधि नहीं देखी गई।

छावनी और सैनिक ठिकानों में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किए गए हैं अनेक उपाय

एजेंसियां

रक्षा मंत्रालय ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों और अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में एक रिपोर्ट एनजीटी के सामने प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट सेना और सियाचिन ग्लेशियर के पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के बारे में थी। जिसे एनजीटी द्वारा 11 फरवरी, 2020 को जारी एक आदेश पर कोर्ट में दायर किया गया है।

रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि उत्तर और पूर्व के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारतीय सेना ने कचरे के निपटान के लिए बड़ी संख्या में पहल की है। लेह और लद्दाख में कचरे को तीन अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जा रहा था। इसके साथ ही परीक्षण के तौर पर सियाचिन ग्लेशियर, लेह, पटसियो, कारू, सरचू, पांग और परतापुर की कुछ चुनिंदा पोस्ट पर मनुष्य द्वारा उत्सर्जित किए जा रहे कचरे के निपटान के लिए बायो-डाइजेस्टर लगाए गए हैं।

जबकि गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे और बचे हुए कचरे के निपटान के लिए पशु पालकों और टट्टुओं की मदद ली जा रही है। राशन की पैकिंग के लिए प्लास्टिक की जगह जूट पैकेजिंग और टेट्रा और रीफिल पैक का उपयोग किया जा रहा है।

वहीं धातु से बनी बैरल और जेरिकैन की जगह एचडीपीई बैरल / जेरिकैन की मदद ली जा रही है। चूंकि यह वजन में हल्की होती हैं, इस वजह से यह कचरे को कम करने में मददगार हो रही हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (डीआरडीई), ग्वालियर ने मानव अपशिष्ट के निपटान के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। जो -40 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर भी कारगर है। वर्तमान में 60 ऐसी इकाइयों को अलग अलग स्थानों पर लगाया गया है। इसी के साथ अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसी तरह के बेहतर दक्षता वाले बायो डाइजेस्टर जारी किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को 9 नवंबर 2020 को एनजीटी की साइट पर अपलोड किया गया है।

धनबाद में सोहराई पेंटिंग प्रतियोगिता सम्पन्न

सिदाम

धनबादः दिनांक 17/11/2020 (मंगलवार)को फागु महतो उच्च विद्यालय, कपुरिया, धनबाद में आदि कुड़मि युवा शक्ति की अनुषांगी छोटानागपुर कुड़मि कला जगत के तत्वावधान में सोहराय परब के उपलक्ष्य में आयोजित सोहराय पेंटिंग प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया। ऑनलाइन हुए इस प्रतियोगिता में देश भर से 80 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विजेताओं के नाम :

ग्रुप 1

प्रथम - निधि रानी, आचार्यकुलम नामकुम, रांची
द्वितीय- सिद्धि महतो, तमाड़, रांची
तृतीय- सुमन कुमारी, नगरीकलां, धनबाद

ग्रुप 2

प्रथम - सुविज्ञा उन्नति बानुआर, कुसुम विहार, धनबाद
द्वितीय - खुशबू कुमारी, बागदाहा, राजगंज, धनबाद
तृतीय - संभवी महतो , नई दिल्ली

ग्रुप 3

प्रथम - सुसेनजीत महतो, पिंड्राजोरा, बोकारो
द्वितीय - कनक कुमार महतो, अद्रकुड़ी, बोकारो

तृतीय - हिमांशु कुमार महतो, धोबोनी, मुनीडीह, धनबाद

विजेताओं का चयन महावीर महतो(शामी), मनीष कुमार महतो, तुलसी महतो, सुरेश केटिआर, कर्मवीर कामदेव, मिहिर केटिआर, राहुल महतो द्वारा किया गया।

इस प्रतियोगिता के आयोजन में छोटानागपुर कुड़मी कला जगत के महावीर महतो(शामी) का अहम योगदान रहा। इस प्रतियोगिता की रूपरेखा उन्होंने हो तैयार की। बाँधडीह ,कपूरिया धनबाद निवासी महावीर महतो(शामी) को पेंटिंग, स्केचिंग, पोस्टर, कैनवास, ऑयल पेंटिंग, कार्टून, वाटर कलर, प्रिंट मेकिंग, वूड कार्विंग, लिनोकट इचिंग, लिथोग्राफी के साथ-साथ सैंड आर्ट में महारथ हासिल है। वर्तमान में जूनागढ़ गुजरात के स्कूल में आर्ट शिक्षक हैं। उनका का कहना है कि ऐसे प्रतियोगता का

उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को मंच देना तथा सोहराई जैसे त्योहार को पेंटिंग में उकेरना है। इस मौके पर मुख्य रूप से कुपुरिया पंचायत के मुखिया सह फागु महतो उच्च विद्यालय के संस्थापक मानगर गजाधर महतो, महावीर महतो,संजय कुमार, अनिल काड़आर, हरे किसनअ हिंदइआर, महेश मुतरुआर,कालीचरण महतो ,मिहिर केटिआर,सुरेश केटिआर ,ओमप्रकाश डुमरियार, मनोहर महतो, राकेश मुकेश बंशीयार, ,संजय बानुआर, संकेत महतो डुंगरियर, मनिंदर महतो केटिआर ,मनीष कुमार महतो, राहुल महतो, महतो कर्मवीर ,नराकेश बानुआर, धीरन महतो,विकास महतो,जवाहर महतो, अजीत महतो, विश्वनाथ महतो आदि उपस्थित रहे।

उत्तराखंड की आबोहवा भी हो रही प्रदूषित

बढ़ते वाहनों और स्थानीय कारणों ने उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य की हवा को भी दूषित कर दिया है। हिमालयी राज्यों के लिए भी वायु प्रदूषण चिंता की वजह बनते जा रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी जिलों की आबोहवा वाहनों से निकलने वाले धुएं की वजह से खराब हो रही है तो पर्वतीय जिलों में कूड़ा जलाने और जंगल की आग जैसी चिंताएं हैं, जो हवा में कार्बन और अन्य जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ा रही हैं। इसके साथ ही पर्वतीय घाटियों की घुमावदार संरचना भी वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव को बढ़ा देती है।

उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण को लेकर इस वर्ष अप्रैल तक के आंकड़े जारी किये हैं। हवा की गुणवत्ता की जांच के लिए बोर्ड के पास देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर और रुद्रपुर में ही मॉनीटरिंग की व्यवस्था है। पर्वतीय जिलों में हवा की गुणवत्ता की जांच की अब तक कोई व्यवस्था ही नहीं है। बोर्ड के मुताबिक देहरादून के घंटाघर क्षेत्र में पीएम-10 का स्तर जनवरी में 165 .25, फरवरी में 182 .59, मार्च में 159 .28 और अप्रैल के महीने में 171.59 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड किया गया। जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक सेहत के लिए हानिकारक है। देहरादून के ही आईएसबीटी क्षेत्र में पीएम-10 की मात्रा जनवरी में सबसे अधिक 243 .12 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स के मुताबिक ये सेहत के लिए अति हानिकार की श्रेणी में आती है।

प्रदूषण के मामले में देहरादून राज्य का सबसे प्रदूषित जिला है। इसके बाद उधमसिंहनगर के रुद्रपुर और काशीपुर का स्थान है। रुद्रपुर में सरकारी अस्पताल के पास अप्रैल महीने में पीएम-10 का स्तर 126 .69 था तो एसपीएम का स्तर 224 .97 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड किया गया। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स कहता है कि हवा में 0-50 तक ही पीएम-10 के स्तर को अच्छा कहा जा सकता है। इस लिहाज से देहरादून की हवा पांच गुना अधिक खराब है। जबकि सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली के आनंदविहार क्षेत्र में हवा में पीएम 10 की मात्रा औसतन 177 और अधिकतम 284 आंकी है।

फोटो न्यूज

पेड़ न काटें : तस्वीर की मार्मिकता बहुत कुछ बता रही है।

वैज्ञानिकों ने पाम ऑयल के कचरे से बनाई इको-फ्रेंडली पैकेजिंग सामग्री

पाम ऑयल के कचरे में 60 फीसदी प्लास्टिक बनाने के गुण पाए गए जो बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग सामग्री बनाने के लिए सबसे अच्छा है।

वर्तमान में प्लास्टिक प्रदूषण का पर्यावरण पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। अब इससे छुटकारा पाने के लिए इसके विकल्प के तौर पर जैव आधारित पॉलिमर का उत्पादन किया जा सकता है, जिसे बायोपॉलिमर के रूप में जाना जाता है। जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। बायोपॉलिमर के उपयोग से गलने वाला (बायोडिग्रेडेबल) प्लास्टिक बनाया जा सकता है। अब वैज्ञानिकों ने पाम ऑयल के कचरे से गलने वाला प्लास्टिक बनाया है। पाम ऑयल उद्योग का विकास व्यापक वनों की कटाई और जीवों के आवासों को तोड़ने से जुड़ा हुआ है। एक शोध जो दोनों मुद्दों को सुलझाने में मदद कर सकता है, जिसमें पाम ऑयल के उत्पादन में बचे कचरे से एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया जा सकता है। पाम ऑयल के कचरे से बने इस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उपयोग खाद्य पैकेजिंग के लिए किया जा सकता है।

जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है उनमें एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक, प्लास्टिक बैग और खाद्य रैपर आदि शामिल है। हर साल उत्पादित होने वाले प्लास्टिक के कचरे का 40 फीसदी के लिए जिम्मेदार हैं। यूनिवर्सिटी सेन्स, मलेशिया के शोधकर्ताओं का कहना है कि हेमीसेलुलोज एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बायोपॉलिमर है, जो पॉलीसैकराइड्स और प्रोटीन जैसे नए पदार्थों से प्राप्त होता है। यह कम लागत, वर्तमान में उपयोग होने वाले प्लास्टिक और पेट्रोलियम आधारित पॉलिमर की जगह ले सकता है। यह शोध करंट रिसर्च के ग्रीन एंड सस्टेनेबल केमिस्ट्री में प्रकाशित हुआ है। प्लास्टिक कचरे के अलावा, केवल मलेशिया में हर साल 1.98 करोड़ (19.8 मिलियन) टन अपशिष्ट पाम ऑयल के फल शेष बच जाते है। कचरे के इस रूप से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए, शोधकर्ताओं ने अपशिष्ट पाम के फलों को हेमिसेल्युलोज में बदल दिया, जिसका उपयोग ग्रीन पैकेजिंग के लिए कर सकते है अर्थात ऐसी पैकेजिंग जिसे उपयोग के बाद नष्ट किया जा सकता है।

प्लास्टिक पैकेजिंग

एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में उत्पादित प्लास्टिक का लगभग एक-तिहाई (128.8 टन) पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लगभग 30 फीसदी प्लास्टिक पैकेजिंग का दुबारा उपयोग नहीं किया जाता है। अनुमानित 10 करोड़ समुद्री जानवर हर साल समुद्र में फैके गए प्लास्टिक के कारण मर जाते हैं। अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक, दुनिया के महासागरों में मछली की तुलना में प्लास्टिक अधिक होगा।

कृषि और बायोमास कचरे में हेमिसेल्युलोज प्रचुर मात्रा में होता है। यह प्लास्टिक बनाने के लिए एक आशाजनक बायोपॉलिमर है क्योंकि यह लचीला है और पानी को रोक सकता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि पाम ऑयल के फलों की पहचान कच्चे माल के रूप में की जा सकती है, जिसका उपयोग ग्रीन पैकेजिंग के लिए किया जा सकता है। इसमें कई गुण हैं जो इसे अन्य बायोपॉलिमरों के लिए एक संभावित विकल्प बनते हैं। इनके कुछ गुण-जैसे इसका आसानी से नष्ट हो जाना।

टीम ने सीएमसी के साथ पाम ऑयल के फलों के रस से विभिन्न मात्रा में हेमिसेल्युलोज को मिलाया। यह तब अलग-अलग मोटाई (सभी एक मिलीमीटर के दसवें भाग के बराबर थे) की बायोपॉलिमर प्लास्टिक बनाया गया। प्लास्टिक की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं की व्यापक जांच से पता चला है कि इसमें 60 फीसदी प्लास्टिक बनाने के गुण पाए गए जो बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग सामग्री बनाने के लिए सबसे अच्छा है। इस नई सामग्री का एक सस्ते और प्रचुर मात्रा में आसानी से नष्ट हो जाने वाली प्लास्टिक बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह प्रदूषित करने वाले प्लास्टिक का एक सबसे अच्छा विकल्प है। यद्यपि पाम ऑयल के उद्योग के कचरे से बायोपॉलिमर्स का उत्पादन करना उद्योग-संबंधी वनों की कटाई को नहीं रोकता है, इससे बने उत्पाद का उपयोग प्लास्टिक प्रदूषण को रोक सकता है। नतीजतन पर्यावरणीय प्रभावों को काफी कम किया जा सकता है।

1990 से एलआरआई ही पांच वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारक

एजेंसियां

तीन दशक में जिस तरह से डायरिया, खसरा जैसे रोगों पर नियंत्रण पाया गया है उस गति में निचले फेफड़ों के संक्रमण से मौतों पर नियंत्रण की कोशिश नहीं हुई है।सरकार भले ही वायु प्रदूषण से मौतों की बात को खारिज करती हो लेकिन जो अपना दुख ठीक से बता नहीं सकते वही वायु प्रदूषण के सबसे बड़े शिकार हैं। पांच वर्ष से छोटी उम्र के बच्चे यदि वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों के कारण मौत के मुंह में जाने से बच जाते हैं तो भी उनकी जिंदगी आसान नहीं रहती। वे घुट-घुट कर जीने को बेबस हैं।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई) और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युशन (आईएचएमई) के संयुक्त अध्ययन ग्लोबल बर्डेन ऑफ डिजीज (जीबीडी), 2017 के दीर्घावधि वाले आंकड़ों के विश्लेषण से यह बात स्पष्ट होती है। 1990 से लेकर 2017 तक पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की प्रमुख बीमारियों से होने वाले मौतों के आंकड़ों का विश्लेषण करने से यह साफ पता चलता है कि जिस तरह से डायरिया, खसरा जैसे रोगों पर नियंत्रण पाया गया है उस गति में निचले फेफड़ों के संक्रमण से मौतों पर नियंत्रण की कोशिश नहीं हुई है। मसलन 1990 में पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की डायरिया से 16.73 फीसदी (4.69 लाख मौतें) हुई थीं जबकि 2017 में नियंत्रण से यह 9.91 फीसदी (एक लाख) पहुंच गईं। वहीं, निचले फेफड़ों के संक्रमण से 1990 में 20.20 फीसदी (5.66 लाख मौतें) हुईं थी जो कि 2017 में 17.9 फीसदी (1.85 लाख) तक ही पहुंची। यानी करीब तीन दशक में एलआरआई से मौतों की फीसदी में गिरावट बेहद मामूली है।

पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की मौत का प्रमुख कारण क्या है? इस सवाल के जबाव में 1990 से 2017 तक के जीबीडी आंकड़ों का विश्लेषण यह बताता है कि पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की मौत का दूसरा सबसे प्रबल कारक निचले फेफड़ों का संक्रमण है। वहीं, निचले फेफड़ों के संक्रमण में वायु प्रदूषण की बड़ी भूमिका है। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 प्रदूषण के वो कण हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते और इतने महीन होते हैं कि श्वास नली के जरिए निचले फेफड़े तक पहुंच जाते हैं। सिर्फ बच्चों में ही यह प्रदूषण कण इसलिए भी ज्यादा प्रभावी होते हैं क्योंकि बच्चे किसी वयस्क के मुकाबले ज्यादा सांस के दौरान ज्यादा प्रदूषण कण भी अपने फेफडों तक पहुंचाते हैं।

जीबीडी के ही आंकड़ों के मुताबिक पांच वर्ष से कम उम्र आयु वर्ग में अब भी अपरिपक्वता, समयपूर्व जन्म, कम वजन का होना, स्वास्थ्य सुविधाओं का न होना जैसे नवजात विकारों के कारण दम तोड़ देते हैं। 28 दिन की उम्र से नीचे यानी नवजात बच्चों की मृत्यु में भी यह कारक प्रमुख हैं। लेकिन जो इस स्टेज को पार कर जाते हैं और पांच वर्ष से छोटे हैं उनमें निचले फेफड़े का संक्रमण होने का जोखिम सबसे ज्यादा है और इसी आयु वर्ग के बच्चे निचले फेफड़े के संक्रमण से दम तोड़ रहे हैं।

जीबीडी, 2017 के आंकड़ों के मुताबिक देश के हर एक घंटे में पांच वर्ष से कम उम्र वाले 21.17 बच्चे निचले फेफड़े के संक्रमण (एलआरआई) के कारण दम तोड़ रहे हैं। इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चे सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं। देश में अब तक के उपलब्ध विस्तृत आंकड़ों के मुताबिक 2017 में 5 वर्ष से कम उम्र वाले 1,035,882.01 बच्चों की मौत विभिन्न रोगों और कारकों से हुई। इनमें 17.9 फीसदी यानी 185,428.53 बच्चे निचले फेफड़ों के संक्रमण के कारण असमय ही मृत्यु की आगोश में चले गए।

नोएडा की 95 ऊंची इमारतें कर रही थी सीवेज प्रदूषण, एनजीटी ने दिए कार्रवाई के आदेश

एजेंसियां

6 नवंबर को एनजीटी में जानकारी दी गई है कि नोएडा के सेक्टर 137 में बिना साफ किये सिंचाई नहर में डाले जा रहे सीवेज को रोकने के लिए जरुरी कार्रवाई की गई है। मामला उत्तर प्रदेश का है। इस सीवेज के लिए मुख्य रूप से नोएडा की 95 ऊंची इमारतों को जिम्मेदार माना गया है। जिनके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) ठीक से काम नहीं कर रहे थे। इनके अलावा कुछ अन्य स्थानों से भी सीवेज प्रदूषण हो रहा था।

नोएडा के लिए वकील ने कहा है कि 95 में से केवल 57 इमारतों का ही निरीक्षण किया गया है। जिसमें भी कई कमियां सामने आई हैं। जिसके विषय में जरुरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

इस बाबत दिल्ली जल बोर्ड के वकील ने कहा है कि उनकी ओर से कार्रवाई की गई है। हालांकि, खोड़ा नगर परिषद, माकनपुर के मामले में पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) और सचिव शहरी विकास, उत्तर प्रदेश की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं ईडीएमसी के वकील का कहना है कि डेयरियों को शिफ्ट करने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन जमीन के अभाव में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। जिसपर एनजीटी ने असंतोष व्यक्त किया है।

इस मामले में एनजीटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए नियमों का पालन किया जाना चाहिए और उसका उल्लंघन करने वालों पर रोक लगाई जानी चाहिए। साथ ही उनपर जुर्माना भी होना चाहिए। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और श्यो कुमार सिंह की पीठ ने निर्देश दिया है कि नोएडा में ऊंची इमारतों के निर्माण के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और सीपीसीबी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट की संयुक्त समिति के द्वारा तीन महीने के अंदर मुआवजे की राशि तय की जानी चाहिए।

भादर नदी को दूषित कर रहे हैं गुजरात के कपड़ा कारखाने

गुजरात के जेतपुर में सभी 3 सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (एसईटीपी) और एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से अपशिष्ट जल का उपचार, कृषि भूमि में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि सभी तीन सीईटीपी और एक एसटीपी से उत्पादित अपशिष्ट जल की मात्रा सिंचाई के लिए उपलब्ध भूमि की तुलना में बहुत अधिक है। यह सब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) की संयुक्त समिति की अनुपालन रिपोर्ट में कहा गया है। यह रिपोर्ट गुजरात के जेतपुर में कपड़ा इकाइयों से निकलने वाले गंदे पानी के कारण भादर नदी में हो रहे प्रदूषण पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुपालन में थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जेतपुर डाइंग एंड प्रिंटिंग एसोसिएशन (जेडीपीए) ने टैंकरों के माध्यम से कपड़ा इकाइयों से अपशिष्ट जल संग्रहण के लिए भादर नदी के किनारे 3 कुओं का निर्माण किया है। कपड़ा इकाइयों ने इन नवनिर्मित कुओं के लिए ज्यादातर टैंकरों के माध्यम से अपशिष्ट को निकालना शुरू कर दिया है। हालांकि यह जेतपुर क्षेत्र से सीवेज और प्राथमिक उपचार जेतपुर के आवासीय क्षेत्र में स्थित कपड़ा इकाइयों से बहता है, जिसे अभी भी खुले सी-चैनल में छोड़ा जा रहा है और नदी के किनारे स्थित संग्रह करने वाले कुंओं में एकत्र किया जाता है। इसलिए भादर नदी के किनारे संग्रह करने वाले कुओं को नष्ट नहीं किया जाता है।

एक बार जब जेतपुर-नवागढ़ नगरपालिका द्वारा 23.5 एमएलडी क्षमता एसटीपी शुरू हो जाती है, तो सी-चैनल में कपड़ा इकाइयों से बहने वाले अपशिष्ट पूरी तरह से बंद होने की संभावना है और जेतपुर क्षेत्र में भादर नदी में अपशिष्ट जल भी नहीं मिलेगा। रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि जेतपुर-नवागढ़ नगरपालिका द्वारा 23.5 एमएलडी एसटीपी का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इसे चालू किया जाए ताकि पूरे क्षेत्र के सीवेज को इस एसटीपी से उपचार किया जा सके और जिससे सी-चैनल में बहने वाले सीवेज को पूरी तरह से बंद किया जा सके। जीपीसीबी और जेडीपीए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि औद्योगिक इकाइयां केवल जेडीपीए के सीईटीपी तक टैंकरों के माध्यम से अपने गंदे पानी का निपटान करें और सी-चैनल में किसी भी प्रकार के गंदे पानी को नहीं छोड़ा जाए।

बंगाली संस्कृति में भूत चतुर्दशी के दिन पकाए जाते हैं 14 शाक

एजेंसियां

एक अध्ययन बताता है कि इन शाकों के सेवन से श्वसन संबंधी मौसमी बीमारियों से तो बचाव के साथ ही दमा, बुखार, गैस्ट्रिक इत्यादि रोगों से बचा जा सकता है। आपने विदेशों में मनाए जाने वाले हैलोवीन फेस्टिवल के बारे में तो सुना ही होगा। दरअसल इस त्योहार को मनाने के पीछे एक मान्यता है कि इस दिन भूत-प्रेत और आत्माएं धरती पर आती हैं, इसलिए इस त्योहार को मनाने के लिए लोग अपने घरों और बच्चों को भूतों की तरह सजाते हैं। इस दौरान पकाए जाने वाले व्यंजनों को भी डरावना आकार दिया जाता है।

यह तो हुई पश्चिमी देशों की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसा ही त्योहार अपने देश में भी मनाया जाता है? भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में दीवाली के एक दिन पहले भूत चतुर्दशी नामक एक त्योहार मनाया जाता है। इस दिन अपने पूर्वजों की याद में 14 दीये जलाए जाते हैं, जिसे चौदह प्रदीप कहा जाता है। साथ ही इस दिन चौदह शाक (साग) नामक व्यंजन भी बनाया जाता है, जिसमें 14 प्रकार के शाक का उपयोग किया जाता है। इन शाकों को जिस पानी से धोया जाता है, उसे पूरे घर में छिड़का जाता है। मान्यता है, कि ऐसा करने से पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है।

भूत चतुर्दशी के दिन पकाए जाने वाले चौदह शाक व्यंजन में जिन शाकों का उपयोग किया जाता है, वे हैं- सूरन के पत्ते (आमोरफोफैलस कंपनुलेटस), बथुआ साग (चेनोपोडियम अल्बम), केउ साग (चीलोकॉस्टस स्पेचीयोसस), कसोंदी साग (कासिया ओक्किडेंटलिस), सरसों साग (ब्रासिका रापा), नीम (अजदिरचता इंडिका), जयंती (सेस्बानिया सेस्बन) गरुंडी (अलतेरननथेरा सेसिलिस), गुरुचि (टिनोसपोरा कोर्डिफोलिया), परवल के पत्ते (ट्रायकोसेंथस दायोका), लसोड़ा (कोर्डिया डायकोटोमा), हिंग्चा साग (एनहाइड्रा फ्लक्यूअंस), घेंटू साग (क्लेरोडेंड्रम स्पलेंडेंस) और सुशनी साग (मर्सेलिया कुआड्रिफोलिया)। हालांकि वर्तमान में इनमें से कई प्रकार के शाक आसानी से नहीं मिल पाते हैं, इसलिए लोग उपलब्धता के अनुसार 14 प्रकार के शाक का उपयोग यह व्यंजन बनाने के लिए करते हैं। 16वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक ''कृत्य-तत्व'' मे रघुनंदन ठाकुर ने पहली बार भूत चतुर्दशी के दिन चौदह शाक खाने की परंपरा का जिक्र एक श्लोक में किया है-

ओलोंग केमुकबास्तुकोंग, सरशोपोंग निंबोंग जोयांग, शलिचिंग हिलमोचिकंचो पोतुकोंग शेलुकोङ्ग गुरुचींतोथा। वोन्तकिंग सुनीशोन्नोकोंग शिब्दीने खादोंती जे मनोबाह, प्रेतोतोंग नो चो जानती कार्तिक दिने कृष्णे चो वुते तिथौ॥

अर्थात, जो लोग कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को 14 प्रकार के शाक खाते हैं, उन्हें प्रेतों की छाया छू भी नहीं सकती।

ऋग्वेद के सूक्त 6/24/4 के अनुसार, पूर्वी भारत में शाकद्वीप नामक एक स्थान था, जहां आर्य निवास करते थे। आर्य लोग भोजन में मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग करते थे, जिन्हें सामूहिक रूप से शाक कहा जाता था। ये लोग बाद में भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर बस गए और साकलद्वीपी ब्राह्मण कहलाए। ऐसी मान्यता है कि शाक चतुर्दशी मनाने की शुरुआत साकलद्वीपी ब्राह्मणों ने ही की थी। महाभारत के 13वें अध्याय के 84वें श्लोक के अनुसार, एक बार युधिष्ठिर भी शाकद्वीप स्थित शाकम्भर तीर्थ गए थे, जहां सिर्फ शाक का सेवन करने वाली शाकम्भरी देवी विराजमान थीं। युधिष्ठिर ने वहां 14 दिनों तक पूजा करने के दौरान शाकंभरी देवी को 14 प्रकार के शाक का भोग लगाया था।

चरक संहिता के अनुसार, शीत ऋतु की शुरुआत में जलवायु में ठंडक और गर्माहट दोनों महसूस होते हैं, ऐसे में सर्दी-जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले सकती हैं। अतः औषधीय गुणों से युक्त शाक-सब्जियों के सेवन से इन बीमारियों से बचा जा सकता है।

विशेष घोल से प्लास्टिक कचरे से अलग हो जाएगा पॉलिमर

एजेंसियां

विस्कॉन्सिन-मैडिसन विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने एक विशेष घोल (सॉल्वैंट) का उपयोग करके अनेक परतों से बनी प्लास्टिक सामग्रियों में से पॉलिमर को निकालने का तरीका विकसित किया है। अनेक परतों से बनी प्लास्टिक सामग्री भोजन और चिकित्सा पैकेजिंग में सबसे अधिक उपयोग की जाती है। क्योंकि पॉलिमर में गर्मी से बचाने या ऑक्सीजन और नमी नियंत्रण जैसे विशिष्ट गुण होते हैं। लेकिन इनके उपयोग के बावजूद मौजूदा प्लास्टिक को पारंपरिक तरीकों से रीसायकल करना असंभव होता है।

लगभग 10 करोड़ टन मल्टीलेयर थर्मोप्लास्टिक, जिसमें हर एक में अलग-अलग पॉलिमर की 12 परतें होती हैं। जिसे दुनिया भर में हर साल उत्पादित किया जाता है। इस पूरे का चालीस प्रतिशत निर्माण प्रक्रिया में ही बर्बाद हो जाता है, क्योंकि पॉलिमर को अलग करने का कोई तरीका नहीं है, इस तरह लगभग सभी प्लास्टिक लैंडफिल या फिर जला दिए जाते हैं। अब अमेरिका की विस्कॉन्सिन-मैडिसन विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने एक विशेष घोल (सॉल्वैंट) का उपयोग करके इन सामग्रियों में से पॉलिमर को फिर से निकालने की एक विधि का विकास किया है।पॉलिमर घुलनशीलता के थर्मोडायनेमिक गणनाओं द्वारा कई बार घोल से साफ किया जाता है, रासायनिक और जैविक इंजीनियरिंग के

यूडब्ल्यू-मैडिसन प्रोफेसर जॉर्ज ह्यूबर और रीड वैन लेहैन ने आम परत वाली सामग्री से बने एक व्यावसायिक प्लास्टिक से पॉलिमर को अलग करने के लिए एसटीआरएपी प्रक्रिया का उपयोग किया। यह सामग्री पॉलीएथिलीन, एथिलीन विनाइल अल्कोहल और पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट से बनी होती है। यह शोध साइंस एडवांसेज में प्रकाशित हुआ है। अलग-अलग पॉलिमर रासायनिक रूप से प्लास्टिक बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं जो एक समान दिखाई देते हैं। टीम को उम्मीद है कि अब नए प्लास्टिक सामग्री बनाने के लिए पुराने सामग्री से फिर से निकाले गए पॉलिमर का उपयोग होगा। यह प्रक्रिया विशेष रूप से अधिक परतों वाली प्लास्टिक निर्माताओं को उत्पादन और पैकेजिंग प्रक्रियाओं के बाद फैंक दी जाने वाली 40 प्रतिशत प्लास्टिक कचरे को दुबारा उपयोग किया जा सकता है।

ह्यूबर कहते हैं कि हमने एक अनेक परतों वाली प्लास्टिक के साथ यह करके दिखाया है। हमें अन्य अधिक परतों वाली प्लास्टिक के साथ यह कोशिश करने की आवश्यकता है और हमें इस तकनीक को और बेहतर करने की आवश्यकता है। चूंकि अनेक परतों से बने प्लास्टिक की जटिलता बढ़ जाती है, इसलिए घोल (सॉल्वैंट्स) की पहचान करने में कठिनाई होती है जो प्रत्येक पॉलिमर को घोल सकती है। इसीलिए स्ट्राप प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वैन लेहन द्वारा उपयोग किए गए कम्प्यूटेशनल दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, जिसे संचालित करने वाले स्क्रीनिंग मॉडल फॉर रियलिस्टिक सॉल्वैंट्स (सीओएसएमओ-आरएस) कहा जाता है।

सीओएसएमओ-आरएस अलग-अलग तापमान पर घोल के मिश्रण में पॉलिमर की घुलनशीलता की गणना कर सकता है, जो संभावित विलायक की संख्या को कम कर सकता है, जो एक पॉलिमर को घोल सकता है। वान लेहन कहते हैं कि यह हमें और अधिक जटिल प्रणालियों से निपटने में मदद कर सकता है, यह वास्तव में रीसाइक्लिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। इसका उद्देश्य एक ऐसी कम्प्यूटेशनल प्रणाली विकसित करना है जो सभी प्रकार के अनेक परतों से बनी प्लास्टिक को रीसायकल करने के लिए विलायक मिश्रण को खोजने में मदद करेगा। टीम ग्रीन सॉल्वैंट्स के एक डेटाबेस का उपयोग करने और इसे बनाने वाले ग्रीन सॉल्वैंट्स के पर्यावरणीय प्रभाव को बहुत कम करने की उम्मीद करती है, जो उन्हें विभिन्न विलायक प्रणालियों की प्रभावशीलता, लागत और पर्यावरणीय प्रभाव को बेहतर ढंग से संतुलित करने में मदद करेगा।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in

Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511

Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm

SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।